



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2003/अग्रहायण 25, 1925

No. 603]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2003/AGRAHAYANA 25, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2003

सा.का.नि. 948(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 23क के खण्ड (ड) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28च की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतनों और भत्तों, और निबंधनों तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और निबंधन तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्राधिकरण' से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28च की उपधारा (1) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 23क के खण्ड (ड) के अधीन गठित सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) 'अध्यक्ष' से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) 'सदस्य' से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;

3. अध्यक्ष का वेतन, भत्ते आदि—(1) अध्यक्ष, मासिक वेतन का उसी दर पर, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है, हकदार होगा :

परन्तु यह कि ऐसा वेतन, पेंशन और किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के समतुल्य पेंशन सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति के पूर्व उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष, ऐसे भत्तों और अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं।

4. सदस्यों का वेतन और भत्ते—सदस्य 22,400-600-26,000 रुपए प्रति मास के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु पूर्वोक्त वर्णित वेतन में से उसके द्वारा ली गई या ली जाने वाली पेंशन और उपदान के समतुल्य पेंशन, अभिदायी निधि में नियोजक के अभिदान या किसी अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी।

5. **मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता**—सदस्य, समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय दरों पर मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करेगा।
6. **छुट्टी** :—अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी छुट्टी का हकदार होगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है :  
परन्तु किसी सदस्य द्वारा सरकार से सेवानिवृत्ति पर भुनाई गई छुट्टी का और प्राधिकरण में अवधि की समाप्ति पर भुनाई जाने वाली छुट्टी कुल तीन सौ दिनों तक निर्बंधित होगी।
7. **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी**—अध्यक्ष, किसी सदस्य को छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी होगा और भारत का राष्ट्रपति, अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी होगा।
8. **पदावधि**—(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की अवधि तक, उस रूप में पद धारण करेगा किन्तु तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।  
परन्तु कोई अध्यक्ष या सदस्य—  
(क) किसी अध्यक्ष की दशा में, सत्तर वर्ष की आयु, और  
(ख) किसी सदस्य की दशा में, बासठ वर्ष की आयु, प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।  
(2) कोई व्यक्ति, सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सेवानिवृत्ति ले लगा और सदस्य के रूप में अपना पद धारण करने के पूर्व सरकारी सेवा से निवृत्त हुआ समझा जाएगा।
9. **अभिदायी भविष्य निधि के लिए अभिदाय**—अध्यक्ष और सदस्य अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो पुनः नियोजित केन्द्रीय सरकार के सेवकों को लागू हैं, अपनी नियुक्ति की तारीख से अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने के हकदार होंगे।
10. **सेवा की अन्य शर्तें**—(1) अध्यक्ष की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 और ऊपर वर्णित अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे। अध्यक्ष, उन सभी भत्तों, परिलब्धियों, विशेषाधिकारों, सुख-सुविधाओं और सुविधाओं का हकदार होगा जो समय-समय पर आसीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को लागू हों।  
(2) सदस्यों की सेवा की शर्तें, उन विषयों के बारे में, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहीं होंगी जो भारत सरकार के अन्य समतुल्य अधिकारियों को लागू होती हैं।
11. **अवशिष्ट उपबंध**—अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा की शर्तों से संबंधित ऐसे विषय, जिनके संबंध में, इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे और उन पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अध्यक्ष या सदस्यों पर आबद्ध होगा।
12. **शिथिल करने की शक्ति**—केन्द्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्गों के संबंध में, इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[सं. 14 फा. सं. 29/2/2000 प्रशा. 1-ग]

प्रशान्त, निदेशक (मुख्यालय)

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2003

**G.S.R.948 (E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 28F of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with clause (e) of Section 23A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the salaries and allowances and terms and conditions of service of Chairperson and Members of the Authority for Advance Rulings for Customs and Central Excise, namely: -

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Authority for Advance Rulings for Customs and Central Excise (Salaries, allowances and terms and conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);

(b) 'Authority' means the Authority for Advance Rulings for Customs and Central Excise constituted under Sub-Section (1) of Section 28F of the Customs Act, 1962 and clause (e) of Section 23A of the Central Excise Act, 1944;

(c) 'Chairperson' means the Chairperson of the Authority;

(d) 'Member' means a Member of the Authority.

**3. Salary, Allowances etcetera of the Chairperson.** - (1) The Chairperson shall be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to a Judge of the Supreme Court :

Provided that such salary, together with the pension and pension equivalent of any other form of retirement benefit, shall not exceed the last pay drawn by him before retirement as a Judge of the Supreme Court.

(2) The Chairperson shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court.

**4. Pay and Allowances etcetera of Members.** - A Member shall receive pay in the scale of Rs.22,400-600-26,000 per month :

Provided that the aforementioned pay shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

**5. Dearness Allowance and City Compensatory Allowance.** - A Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance at the rates admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

**6. Leave.** - A person appointed as Chairperson or Member shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Central Government under Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 :

Provided that the encashment of leave taken on retirement from Government by a Member and the leave to be encashed at the end of the tenure in the Authority shall be restricted to a total of 300 days.

**7. Leave Sanctioning Authority.** - The Chairperson shall be the authority competent to sanction leave to a Member and the President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

**8. Term of Office.** - (1) The Chairperson or a Member shall hold office as such for a term of three years from the date on which he enters upon his office but shall be eligible for re-appointment for another term of three years :

Provided that no Chairperson or Member shall hold office as such after he has attained -

(a) in the case of any Chairperson, the age of seventy years, and

(b) in the case of any Member, the age of sixty two years.

(2) A person, when appointed as a Member, shall seek retirement and shall be deemed to have retired from Government service before he enters upon his office as a Member.

**9. Contribution to Contributory Provident Fund.** - The Chairperson and Members shall be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund from the date of their appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants.

**10. Other Conditions of Service.** - (1) The conditions of service of Chairperson, for which no provision is made in these rules, shall be governed by the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), and the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959 and the Rules framed under the above mentioned Act. The Chairperson shall also be entitled to all allowances, perquisites, privileges, amenities and facilities as are admissible to sitting Judges of the Supreme Court from time to time.

(2) The conditions of service of Members in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as may be applicable to other equivalent officers of the Government of India.

**11. Residuary Provisions.** - Matters relating to the conditions of service of the Chairperson or the Members with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Chairperson or the Members.

**12. Powers to Relax.** - The Central Government shall have the power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No.14 F.No.29/2000-Ad.I-C]

PRASHANT, Director (Hqrs.)